खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) जी हां, जुलाई, 1990 से अक्तूबर, 1990 तक दिल्ली में लोकप्रिय ब्रांडों के वनस्पति के मूल्यों में लगभग 17 प्रतिशत वृद्धि हुई थी ।

(ख) जी हां ।

(ग) दिल्ली में रथ और डालडा वनस्पति की 1 कि. ग्रा. की थैली के मूल्य दिनांक 31 अक्तूबर, 1990 को क्रमशः 38.65 रुपये और 39.30 रुपये थे ।

(घ) सरकार द्वारा कीमतों को कम करने के लिए उठाए गए कुछ प्रशासनिक कदम इस प्रकार हैं :—

1. वनस्पति के विनिर्माण में लघु/गैर-परम्परागत तेलों के प्रयोग पर उत्पाद शुल्क में छूट दी गई है ;

2. थोक और खुदरा विक्रेताओं के पास हाइड्रोजनित वनस्पति तेलों की स्टाक सीमा घटाई गई है ;

3. उत्पादकों के पास खाद्य तेलों और वनस्पति की स्टाक सीमाएं घटा दी गई है ;

4. कम की गई स्टाक सीमाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित आधार पर जमाखोरी विरोधी अभियान चलाएं ।

दिल्ली हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी समिति द्वारा सहकारी आवास समितियों को ऋण

1137. **श्री बलराम सिंह यादव :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 दिसम्बर, 1990 को जनसत्ता में "जब कर्ज ही नहीं मिलेगा तो मकान कहां से बनेंगे" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल में दिल्ली की लगभग 400 सहकारी आवास समितियों को भूमि के आवंटन के बारे में अपनी योजना को कार्यान्वित किया है जब कि दिल्ली हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी ने आवास निर्माण के लिये केवल 250 करोड़ रुपये की ऋण राशि ही निर्धारित की है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऋण की राशि बढ़ाने का विचार रखती है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और प्रत्येक समिति को हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी द्वारा ऋण की कितनी-कितनी राशि दिए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में 423 सहकारिता सामूहिक आवास समितियों को पप्पनकलां/नरेला में भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव-पत्र भेजे हैं ।

दिल्ली सहकारी आवास वित्त समिति लिमिटेड ने, जो कि सहकारी सामूहिक आवास समितियों की ऋण आवश्यकताएं पूरी करता हैं, आठवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं से निधि की पूर्वानुमानित उपलब्धता के आधार पर 250 करोड़ रुपये की राशि उद्दिष्ट की है । सहकारी सामूहिक आवास समितियों की ऋण आवश्यकता पूरी करने वाली यह अकेली संस्था नहीं है । जीवन बीमानिगम, आवास वित्त निगम, हुडको, एच. डी. एफ. सी., कैन फाइनेन्स होम बैंक इत्यादि जैसी अन्य संस्थाएं भी हैं जो सहकारी सामूहिक आवास समितियों की ऋण आवश्यकताओं को पूरी करती हैं । सरकार ने भी देश में आवास वित्त संस्थाओं के कार्यकलापों में

समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक का गठन किया है ।

Gap between Demand and Supply of Edible Oils

1138. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state;

(a) what was the overall defieit in supply of the edible oils at the end of 1989 and October, 1990;

(b) what is the overall domestic oilseeds production anticipated in the rabi cropping season and to what extent the shortfall, if any, in production of oilseeds in last Kharif Crop is likely to be made up;

(c) what is anticipated net gap between demand and supply of edible oils;

(d) whether Government propose to import edible oils to cover the deficit; and also the other measures to meet the shortage;

(e) if so, the quantity of edible oils with value in foreign exchange likely to be imported; and

(f) what is the anticipated overall impact as a result of imports on the prices of edible oils?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI JAYANTILAL VIRCHAND-BHAI SHAH); (a) In Oil Year 1989-90 (1. 11. 89- 30-10-90) the overall deficit in supply of edible oils as" compared to demand was approxima-"" •. *tely 9. 1* lakh tonnes.

(b) The target for oilseeds production in the rabi season is 80 lakh tonnes. Rabi prospects are favourable but any firm estimates of the rabi crop at the present stage would be premature.

Oc) The gap can be computed only after firm estimates of the rabi crop are available,

(d) Apart from import of edible oils, efforts to enhance production through the Oilseeds production Programme (OPP) and measures to increase the efficiency of oilseeds processing; and extraction are being taken.

(e) The quantity of edible oil likely to be imported and its value in foreign exchange will depend on the domestic production of edible oil. availability of foreign exchange and oil prices in the international markets. The matter s being constantly reviewed and hence it is not possible to precisely indicate the quantity likely to be imported.

(f) The open market prices of edible oil rise due to factors such as shortfall in indigenous production, increase in support prices,. upward revision in prices of petroleum products, increase in railway freight, comulative effect of increase in money supply and increase in consumer in money supply and increase in consumer demand. The import of edible oil is undertaken with a view to increasing availability and thereby checkng price rises

भूमि सुधारों का कार्यान्वयन

1139. **श्री राम नरेश यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में भूमि सुधारों का तत्काल कार्यान्वयन करने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) और (ख) भूमि राज्य का विषय होने के नाते भूमि सुधारों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, भूमि सुधार उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु भूमि कानूनों